महिला उद्यमियों की राहें होंगी आसान, उद्योगों में भी बनाएंगे वीमेन हेल्प डेस्क

अमर उजाला व आईसीएआई के उद्यमिता को सलाम कार्यक्रम में बोले- एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन प्रयासों से महिला उद्यमियों की राहें आसान होंगी। उन्होंने कहा कि अब उद्योगों में भी वीमेन हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। वे सोमवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गोमतीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की लखनऊ शाखा व अमर उजाला की ओर से हुए 'उद्यमिता को सलाम' कार्यक्रम में बोल रहे थे।

आईसीएआई सभागार में हुए इस कार्यक्रम के तहत एमएसएमई से महिलाओं को भागीदारी विषयक संवाद व सम्मान समारोह में सिद्धार्थनाथ ने कहा कि सरकार के प्रयासों से 41,244 हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से महिलाएं अपनी समस्याएं रख सकती हैं। ये हेल्प डेस्क उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगी। जानता इस बात को है कि समाज के सभी तबके की महिलाएं उद्योगों में प्रमोशन महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे आएं। अगला सूद का लाभ जैसे मुद्रा फंडिंग, टेक्नीकल आदि योजनाओं के लिए सरकार महिलाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण मुहैया करा रही है, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भी दे रही है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गोमतीनगर स्थित आईसीएआई की लखनऊ शाखा व अमर उजाला की ओर से हुए कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री महिलाओं की भागीदारी विषयक संवाद में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने महिला उद्यमियों के सवालों का जवाब दिया। फोटो : अमर उजाला

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में अब तक 21,650 महिलाओं को इनके घनघोरा क्षेत्र में व्यवसाय शुरू कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद सरकार ने उनको टूलकिट और धन भी मुहैया कराया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफल महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

- **कार्यक्रम में 121 लाख से ज्यादा महिला उद्यमी हैं।** एमएसएमई के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 220 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अभी प्रदेश महिलाओं की भागीदारी कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है।
- उन्होंने नोट इंस्टीट्यूट का आभार किया कि वे इस दिशा में मदद कर सकते हैं। प्रदेश महिलाओं को लोन संबंधी, बैंक के अन्य कार्य व उद्योगों को स्थापित करने संबंधी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

अगला व्यवसाय शुरू कराने के लिए महिलाओं को सरकार की तरफ से धन भी मुहैया कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कई स्कीम संचालित हैं। इस दौरान अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने महिलाओं के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि कैसे नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार की स्कीम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में आईसीएआई लखनऊ शाखा के अध्यक्ष प्रदीप गोयल, पूर्व गोमतीनगर स्टूडेंट चार्ट और मनिष दीपक चौधरी ने एमएसएमई मंत्री व अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल को सम्मानित किया।

रूढ़िवादी विचारों को तोड़ रही सरकार : सहगल

अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने कहा कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर कार्य नहीं कर सकतीं, इस मान्यता को तोड़ने का सरकार पूरजोर प्रयास कर रही है। समाज को अपनी अलग इकाई भागीदारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जो शहर की महिला उद्यमी हैं वे महिलाओं का समूह बनाकर उनकी जागरूकता ला सकती हैं। कई संस्थाएं सक्रीय हैं, उनमें किस तरह का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, कहां से फंड मिलेगी, इन सब बातों को महिला उद्यमी बाकी महिलाओं को जानकारी देकर जागरूक बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोगों से उद्यम स्थापित करने व संस्थाओं का हल निकालने के लिए उद्यम आयोग समेत कई तरह के एप लांच किए हैं। इसके माध्यम से घरेलू व कारीगर किए जा सकते हैं, उसके लिए किस तरह का पैकेज बनाने चाहिए, इसकी जानकारी ली जा सकती है। सरकार इसके लिए 15 करोड़ रुपये तक का प्रोटो उपलब्ध कराती है। इसका 50 प्रतिशत सरकार वहन कराती है।